



देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 05

अंक - 74

जौनपुर, शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

डेयरी क्षेत्र को मजबूत करेगा असम, रोजना 10 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसका लक्ष्य प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करना है। इसके साथ ही, डेयरी किसानों को सीधी सब्सिडी दी जाएगी और प्रोसेसिंग इफ्रास्ट्रक्चर (प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे) का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "एक मजबूत डेयरी क्षेत्र से पोषण में सुधार होगा, किसानों की आजीविका सुरक्षित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी।" उन्होंने इन पहलों को 'आत्मनिर्भर असम' बनाने की राज्य की कोशिशों का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने और डेयरी सप्लाई चेन में सुधार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सरमा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य ने प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने और किसानों की आय में मदद करने के लिए उन्हें सीधे दूध पर सब्सिडी दे रही है। राज्य पूरे असम में बड़े डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन सुविधाओं से दूध प्रोसेसिंग क्षमता मजबूत होगी।

ऊर्जा लक्ष्य के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश की जरूरत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत को अपने 500 गीगावाट की वलीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जलवायु निवेश, अनुकूलन वित्त (अडैप्टेशन फाइनेंस), टेक्नोलॉजी सहयोग और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जानकारी तुर्किए में होने वाली कॉप31 क्लाइमेट समिट से पहले इंडस्ट्री चौम्बर्स की ओर से दी गई। इंडस्ट्री चौम्बर्स एसोसिएम ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की बढ़ोतरी के साथ, जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 300.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। बयान के अनुसार, भारत ने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही अपनी कुल बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक कर ली है। एसोसिएम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने कहा, "देश ने यह साबित कर दिया है कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था स्वच्छ ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपना सकती है। भारत ने तय समय से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कॉप31 में अमल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें उद्योग जगत की मुख्य भूमिका हो।

आखिरी सांस तक देश की सेवा करता रहूंगा - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात और देश के लोगों की सेवा करना ही उनके सफर का मुख्य केंद्र रहा है। उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने के लिए नागरिकों का आभार जताया और अपनी उपलब्धियों को उन्हें समर्पित किया। बनावसकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसके परिवार की पीढ़ियों ने कभी गांव का मुखिया बनने की भी कल्पना नहीं की थीकुउसे गुजरात और बाद में पूरे देश की सेवा करने का अवसर मिला। पीएम ने कहा कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसके परिवार की पीढ़ियों ने कभी गांव का मुखिया बनने का सपना तक नहीं देखा थाकुउसे आपने इस योग्य



समझा। आपने मुझे पहले गुजरात और फिर पूरे देश की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही राष्ट्र सेवा है, और गुजरात का विकास देश के विकास में योगदान देता है। राष्ट्र के लिए मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उसका श्रेय मेरे सभी देशवासियों को जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। और अपने

जीवन के अंतिम क्षण तक, मैं आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। कृषि और सहकारी क्षेत्र में बनावसकांठा के योगदान का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पैदा होने वाले आलू को वैश्विक पहचान मिली है। साथ ही, उन्होंने गुजरात के बाहर सहकारी आंदोलन का विस्तार करने के लिए बनावस डेयरी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने

उत्तर प्रदेश में सुधरी कानून व्यवस्था, महिला श्रम भागीदारी 36 फीसदी पहुंची - सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य की बेहतर कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में रात के समय जगमगाते बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यापारियों के बढ़ते विश्वास के प्रतीक हैं। योगी ने दावा किया कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के साथ उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में योगी ने कहा कि रात्रिकालीन पाली में महिलाएं निर्भय होकर कार्यस्थलों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उनका आत्मविश्वास पूरे समाज की प्रगति का प्रतीक है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अपराध और अपराधियों का सामना करना पड़ता था। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपराध और अपराधियों



के प्रति कर्तई बर्दाश्त नहीं की नीति अपनाकर कानून-व्यवस्था मजबूत की और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं, व्यापारियों को कारोबार विस्तार के अवसर मिल रहे हैं और महिलाएं सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ रही हैं। इसे उन्होंने महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, आर्थिक सामर्थ्य और स्वावलंबन के साथ सुरक्षा से समृद्धि की ओर बढ़ते गए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया।

10वें दीपोत्सव में दूहेगा भव्यता का हर रिकॉर्ड, गुलाबी पत्थरों से जगमगाएगी राम की पैड़ी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रामनगरी में योगी सरकार का 10वां दीपोत्सव 7 नवंबर को अयोध्या में मनाया जाएगा। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी को संवारने और सजाने का काम तेज गति से चल रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। राम की पैड़ी पर इस बार पांच हजार से ज्यादा आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए तीन अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। साथ ही एक विशाल सेट का निर्माण भी कराया जा रहा है। राम की पैड़ी पर राजस्थान के धौलपुर के गहरे गुलाबी पत्थर बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। 2017 में योगी सरकार के बनने के बाद से हर साल दीपोत्सव और भी भव्य होता जा रहा है। दीपोत्सव ने अयोध्या की छवि को देश दुनिया में निखारा है। इस बार राम की पैड़ी पर धौलपुर के पत्थर



बिछाए ही नहीं जा रहे, बल्कि इन्हीं पत्थरों से सेल्फी प्वाइंट के लिए राजस्थानी संस्कृति मंडप का निर्माण भी किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर 10 मंडप तैयार किए गए हैं। इनकी खासियत है कि पर्यटक यहां बैठकर राम की पैड़ी की सुंदरता निहार सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं। धौलपुर के गुलाबी पत्थरों की खासियत है कि ये जितने घिसते हैं, उतनी ही इनमें चमक आती है और ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। इस बार पिछले दीपोत्सव से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया

जा रहा है। ये वीआईपी अतिथि विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, जिनमें कई देशों के मेहमान भी शामिल होंगे। इनके बैठने के लिए तीन अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जिन्हें आमंत्रण भेजा गया है। मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि के लिए 52 गुने 28 का विशाल मंच बनाया गया है। दूसरा मंच 16 गुने 40 का बनाया जा रहा है, जिसमें साधु संत

सीएम विजय ने उम्र सीमा में दी पांच साल की छूट

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह निर्देश अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, जो निर्धारित आयु सीमा पार होने के कारण सरकारी भर्तियों में आवेदन करने का मौका गंवा देते हैं। अब उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के वास्ते पांच साल की अतिरिक्त आयु सीमा का लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय का यह निर्देश पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। यानी इस दौरान सरकारी नौकरी की भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अलावा पांच साल की अतिरिक्त



छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन के अधिक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग भर्तियों में इस छूट को लागू करने से जुड़े विस्तृत नियम और पात्रता की जानकारी संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगी।

कहा कि आज बनावसकांठा के आलू दुनिया भर में मशहूर हैं। और कोई भी व्यक्ति बनावसकांठा के लोगों के पास आकर यह दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह आलू को सोने में बदल सकता है। क्योंकि वे खुद ही ऐसा कर रहे हैं। यहाँ खनास डेयरीश जैसा एक सहकारी ब्रांड है, जो सहकारी आंदोलन को न केवल यहाँ, बल्कि काशी सहित देश के अन्य हिस्सों में भी आगे बढ़ा रहा है। मैं बनावस डेयरी का विशेष रूप से आभारी हूँ, क्योंकि आपके अनुभव और आपकी सेवाओं से मेरी काशी को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने आलू प्रसंस्करण संयंत्र (चवर्जजव चतवर्भेमपदह चसंदज) की क्षमता बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि इससे आलू की अधिक मात्रा में खरीद हो सकेगी।

अमित शाह ने सपा को दिलाई रामभक्तों पर गोलीकांड की याद

लखनऊ, (संवाददाता)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान अयोध्या में राम भक्तों पर हुई गोलीबारी का जिक्र किया और दावा किया कि राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में यूपी भाजपा की कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, शाह ने उन्हें भाजपा का मालिक बताया और सम्मानपूर्वक धाम-राम कहकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और 2017 तथा 2022 के



विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को याद किया। समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या गोलीकांड का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोलीबारी हुई थी, जिससे सरपू नदी रक्त-रंजित हो गई थी। अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि वे किस आधार पर प्रदेश में सत्ता में वापसी का

दावा कर रहे हैं। शाह ने भाजपा की उपस्थिति को अटल बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की जड़ें अंगद के पैर की भांति अडिग हैं और आगामी चुनावों में भाजपा पुनः बहुमत हासिल करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के योगदान को उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता की परवाह किए बिना अयोध्या में कारसेवा का मार्ग प्रशस्त किया था। शाह ने कहा कि वह

धूमधाम मचाने वाले धड़ाम से गिरे, भाजपा पांच सीट नहीं 50 जिलों में हारी - अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी विधान परिषद चुनाव में 5 सीटों पर जीत से उत्साहित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि ये धूमधाम मचाने वाले लोग इन चुनाव में धड़ाम से गिर गए। भाजपा सिर्फ 5 सीट ही नहीं हारी है बल्कि 50 जिलों में हारी है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा जनता के समर्थन से जीती है जबकि जनता में संदेश ये गया है कि भाजपा ने इन चुनाव में छल करके छह सीटें जीती हैं। जहां साजिश है। वहीं, भाजपा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने बेईमानी से छह सीटें जीती हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव होते तो भाजपा की जीत ऐसी न होती। उन्होंने विधान परिषद के सभी विजयी सदस्यों को बधाई दी। इस जीत से साबित हो गया है कि व्यापारी हमारे साथ हैं। आधी आबादी हमारे साथ है। उन्होंने वाराणसी की सीटों पर हार को लेकर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कि काशी भले ही डूब जाए पर गोरखधंधा बंद न हो। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने वाराणसी में भाजपा की हार पर कहा कि वाराणसी में डबल इंजन की डबल हार हुई है। इन चुनाव में महिला शिक्षकों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने कहा कि अब कई अफसरों पर गाज गिरने वाली है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में अनियमितता के आरोप भी लगाए और अमरोहा में 94 प्रतिशत मतदान पर सवाल उठाए।



पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, चांद के दीदार के बाद पूरा हुआ पूजन

अयोध्या(DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ का पर्व गुरुवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन व्रत महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को चंद्रमा के दर्शन और विधि-विधान से पूजन करने के बाद पानी पीकर अपना व्रत खोला। इस भावुक और आत्मीय पल में दंपती के बीच प्रेम, विश्वास और पारिवारिक समर्पण की झलक देखने को मिली। करवा चौथ केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण को और मजबूत करने का अवसर है। यह त्योहार भारतीय परंपराओं और पारिवारिक



संस्कारों की खूबसूरती को दर्शाता है। हर दांपत्य जीवन में आपसी सम्मान, समझ और विश्वास बना रहना सबसे जरूरी है। यही रिश्ते की असली मजबूती है। करवा चौथ का पर्व पति-पत्नी के बीच स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। पत्नी द्वारा परिवार की खुशहाली और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला व्रत उनके प्रेम और समर्पण को



दर्शाता है। जीवनसाथी का साथ, सम्मान और विश्वास ही सुखी वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे पर्व हमें अपनी परंपराओं से जोड़ने के साथ रिश्तों की अहमियत भी समझाते हैं। गौरतलब है कि करवा चौथ हिंदू महिलाओं के प्रमुख व्रत-त्योहारों में शामिल है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखकर

भगवान गणेश, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं तथा पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के साथ व्रत पूरा किया जाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, आस्था और वैवाहिक रिश्तों की मजबूती का सुंदर संदेश देता है।

संपादकीय

केंद्र मे फिर से खड़ी सरकार

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराड़ीसैण में 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित विधानसभा सत्र ने एक बार फिर राज्य की राजधानी को सवाल को गंभीर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। दो दिनों के लिए आयोजित विधानसभा की वास्तविक कार्यवाही मात्र आठ घंटे चार मिनट चली। पहले दिन छह घंटे 58 मिनट और दूसरे दिन केवल एक घंटा छह मिनट। इस बीच 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूर्क बजट और 9 विधेयक पारित हो गए, लेकिन जनता की समस्याओं पर अपेक्षित गंभीर चर्चा नहीं हो सकी। दूसरे दिन प्रश्नकाल भी विषक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाल केवल इतने कम समय तक विधानसभा चलने का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जिस स्थान को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, वहां सरकार और विधायिका की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के बजाय कुछ घंटों की संसदीय गतिविधियों को राजधानी की सार्थकता का प्रमाण क्यों माना जाए? भराड़ीसैण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है। सरकारी वाहनों, आवास, भोजन, सुरक्षा, संचार, बिजली, पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक धन खर्च होता है। इस सत्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई, इसका प्रमाणित और मदवार विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। बिना अधिकृत लेखे के करोड़ों रुपये का कोई निश्चित आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा। लेकिन खर्च की वास्तविक राशि चाहे जितनी हो, उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन आवश्यक है। लोकतंत्र में सार्वजनिक व्यय का औचित्य केवल संवैध ानिक प्रक्रिया पूरी करने से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाले परिणामों से भी निर्धारित होता है। गैरसैण या भराड़ीसैण कोई सामान्य कस्बा नहीं है, जहां कभी—कभार विधानसभा की बैठक आयोजित कर देने से राजनीतिक दायित्व पूरा मान लिया जाए। यह उत्तराखंड राज्य आंदोलन की उस अवधारणा का प्रतीक है, जिसमें अलग राज्य का अर्थ केवल उत्तर प्रदेश से प्रशासनिक विभाजन नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करना था। आंदोलनकारियों की कल्पना में राजधानी केवल सत्ता के प्रतिष्ठानों का समूह नहीं, बल्कि शासन को पहाड़ के निकट लाने का माध्यम थी। उत्तराखंड के गठन से पहले ही गैरसैण राजधानी के विकल्प के रूप में उभर चुका था। राज्य आंदोलन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति को विशेष महत्व दिया गया। वर्ष 2000 में राज्य बनने पर देहरादून को अंतरिम राजधानी बनाया गया। इसके पीछे तत्काल उपलब्ध प्रशासनिक सुविधाओं और संपर्क व्यवस्था का तर्क था। बाद में स्थायी राजधानी के प्रश्न पर आयोगों और समितियों के माध्यम से विचार हुआ, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी। वर्ष 2020 में गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। इसके बावजूद शासन का वास्तविक केंद्र देहरादून ही बना हुआ है। राजधानी के सवाल पर उत्तराखंड की राजनीति में एक विचित्र विरोधाभास दिखाई देता है। विभिन्न राजनीतिक दल गैरसैण के महत्व को स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन उसे प्रशासनिक रूप से सक्षम राजधानी बनाने की दिशा में अपेक्षित निरंतरता नहीं दिखाई देती।

डीपफेक के दौर में राजनीति

विनोद पिछले दिनों एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। पहली नजर में यह वास्तविक प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसमें किए गए दावे और उसकी भाषा संदेह पैदा करने वाले थे। विडंबना यह रही कि वीडियो के फर्जी होने के बावजूद विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे साझा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी वीडियो को बिना सत्यापन प्रसारित करना महज राजनीतिक चूक नहीं, बल्कि देश की सामरिक विश्वसनीयता, सेना के मनोबल और जनविश्वास के लिए गंभीर चुनौती है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना है। चीन की गतिविधियों, सीमाओं की सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और सैनिकों को उपलब्ध सुविधाओं पर सवाल उठाना उसका अधिकार है। सरकार की नीतियों में कमी हो तो उसे सामने लाना भी जरूरी है, लेकिन सरकार की आलोचना और अपुष्ट सामग्री को प्रमाण की तरह प्रसारित करना दो अलग बातें हैं। पहली लोकांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है, जबकि दूसरी सार्वजनिक विमर्श को गलत सूचना की गिरफ्त में ले जा सकती है। समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब किसी सूचना की सत्यता से अधिक उसके राजनीतिक उपयोग को महत्व मिलने लगता है। सरकार को कठघरे में खड़ा करने की जल्दबाजी में क्या यह देखना जरूरी नहीं कि वीडियो वास्तविक है या फर्जी? क्या किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के नाम से प्रसारित बयान को केवल इसलिए सच मान लिया जाए कि वह राजनीतिक आरोपों को बल देता है? किसी गंभीर आरोप को सार्वजनिक करने से पहले मूल वीडियो, संबंधित अधिकारी का वास्तविक बयान और आधिकारिक स्पष्टीकरण देखना सामान्य सावध ानी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के पास संसाधन, शोधकर्ता और संचार तंत्र उपलब्ध हैं। इसलिए उनसे तथ्य—जांच के मामले में अड़िाक जिम्मेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से दुष्प्रचार की आशंकाएं नई नहीं हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे, पुराने वीडियो और कथित सैन्य घटनाओं से जुड़ी झूठी सामग्री प्रसारित होती रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी फैंट—चेक इकाइयों ने समय—समय पर ऐसी सामग्री का खंडन किया है। डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब किसी वास्तविक सैन्य अधिकारी के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके ऐसा बयान तैयार किया जा सकता है, जो उसने कभी दिया ही नहीं। ऐसे दुष्प्रचार का उद्देश्य केवल झूठी खबर फैलाना नहीं होता। इसके जरिए सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने और जनता के मन में देश की सैन्य स्थिति को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। यदि ऐसी सामग्री को देश के भीतर प्रभावशाली राजनीतिक आवाजों का सहारा मिल जाए, तो उसकी पहुंच और विश्वसनीयता का भ्रम दोनों बढ़ सकते हैं। विदेशी दुष्प्रचार तंत्र के लिए इससे अनुकूल स्थिति और क्या होगी कि उसके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू राजनीतिक मंच भी उपलब्ध हो जाए? यहीं विपक्षी नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। यदि कोई नेता बिना सत्यापन ऐसी सामग्री साझा करता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह जानबूझकर पाकिस्तान या किसी विदेशी एजेंसी के एजेंडे पर काम कर रहा है। किसी की नीयत पर आरोप लगाने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। लेकिन उसकी राजनीतिक और सार्वजनिक जिम्मेदारी का मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए। क्या वीडियो साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांची गई थी? यदि नहीं, तो क्या गलती सामने आने पर उसे स्वीकार किया गया? क्या लोगों को बताया गया कि साझा की गई सामग्री भ्रामक निकली? प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों की सोशल मीडिया पर व्यापक पहुंच होती है। उनके एक संदेश को लाखों लोग देख सकते हैं, जबकि उसका खंडन शायद उतने लोगों तक कभी न पहुंचे। इसलिए किसी गलत दावे को साझा करने के बाद केवल पोस्ट हटा देना पर्याप्त नहीं होना चाहिए।

विचार

कुपोषण से लड़ने का एक प्रभावी हथियार

संजय पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन में तेजी से प्रगति के बावजूद, भारत को अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) की कमी शामिल है, जिसे विशेषज्ञ छिपी हुई भूख (हिडन हंगर) कहते हैं। 1960 के दशक की हर्षित क्रांति ने, जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों और बेहतर कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद तो की, लेकिन अड़िाक उपज पर जोर देने के चक्कर में अक्सर पोषण की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ा। आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता भी अभी काफी कम है। यहीं पर बायोफोर्टिफिकेशन कुपोषण से निपटने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। फसल बायोफोर्टिफिकेशन – यानी खेती के



दौरान ही फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया।कृएक टिकाऊ, किकायती और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। इसमें पारंपरिक पादप प्रजनन के जरिए खाद्य फसलों में आयरन, जिक, विटामिन । और प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर उनकी पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इंडस्ट्रियल फोर्टिफि केशन (जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्व मिलाए जाते हैं) या स्प्लीमेंटेशन (जिसमें गोलियों के जरिए पोषक

तत्व दिए जाते हैं) के विपरीत, बायोफोर्टिफिकेशन का लक्ष्य फसलों को प्राकृतिक रूप से ही जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। भारत में 60: से अधिक लोग अनाज पर आध्ारित आहार लेते हैं। अगर मुख्य खाद्य पदार्थों में ही आयरन, जिक या प्रोटीन मौजूद हों, तो लोगों को अपनी खान–पान की आदतों में कोई बड़ा बदलाव किए बिना, रोजमर्रा के भोजन के जरिए ये पोषक तत्व मिल सकते हैं। हाल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता

डेटा सेंटर नीति में जल स्थिरता को प्राथमिकता देना जरूरी

हार्ड—परफॉर्मंस कंप्यूटिंग की मांग के साथ यह मुद्दा और भी अहम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 में 375 डें से बढ़कर 2025 तक 1,500 डें से अधिक हो गई है। सरकार पानी और ऊर्जा बचाने के लिए नई तकनीकों पर भी जोर दे रही है, जैसे कि डायरेक्ट—डू—चिप लिक्विड कूलिंग, इमर्शन कूलिंग और एडियाबेटिक कूलिंग। कोई एक आंकड़ा सभी डेटा सेंटरों के श्वॉटर फुटप्रिंटस् (पानी की खपत) को सही ढंग से नहीं दिखा सकता। पानी की खपत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जलवायु, कूलिंग तकनीक, सर्वर की सघनता (डेंसिटी) और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। वॉटर यूसेज इफेक्टिवनेस एक नया पैमाना है जो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कर्नाटक की नई नीति में wueऔर पावर यूसेज इफेक्टिवनेस की निगरानी करने का प्रस्ताव है। यह एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि, इन पैमानों का सही मतलब तभी निकलेगा, जब इनका इस्तेमाल यह तय करने में भी किया जाए कि डेटा सेंटर कहाँ और कैसे बनाए जाएं।

कर्नाटक की दुविधा समय बहुत मायने रखता है। कर्नाटक एक तरफ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। सर्वर से गर्मी पैदा होती है, इसलिए कूलिंग बहुत जरूरी है। तकनीक और काम करने की स्थितियों के आधार पर, कूलिंग के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्टें से पता चलता है कि राज्य ने 25 वर्षों में 17वीं बार सूखे की घोषणा की है, जो कई इलाकों में पानी की दुविधा

समय बहुत मायने रखता है। कर्नाटक एक तरफ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। सर्वर से गर्मी पैदा होती है, इसलिए कूलिंग बहुत जरूरी है। तकनीक और काम करने की स्थितियों के आधार पर, कूलिंग के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्टें से पता चलता है कि राज्य ने 25 वर्षों में 17वीं बार सूखे की घोषणा की है, जो कई इलाकों

यूरोप में यूपी के ‘योगी मॉडल’ पर अमल के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

तत्पश्चात मोदी के दूसरे मित्र फ्रांस के प्रमुख मैक्रो ने जब यूपी के योगी मॉडल की अच्छी नीतियों पर अमल करना शुरु किया तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार श्रंगैश सक्रिय हो गया और यूरोपीय देशों को उस नकारा लोकतंत्र की दुहाई देने लगा, जहां फ्रांस के बेलगाम लोग श्जुलीन पूंजीवादी नियंत्रण, प्रशासनिक सख्ती और अवैै अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसी नीतियों के लिए किया जाता है। हालाँकि, इन सभी उपायों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है। अपराध की जाँच, दोषसिद्धि, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा अलग—अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। चूंकि यूपी में बेलगाम अल्पसंख्यक अपराधियों, सत्ता प्रशिक्षित बाहुबलियों, इनसे जुड़े मनबढ़ युवाओं और शांति अपराधियों के इशारे पर अपराध कर रहे बहुसंख्यक अपराधियों को नियंत्रित करने में यूपी के योगी मॉडल ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, इसलिए चारो तरफ से जल रहे फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। सर्वप्रथम इटली की प्रमुख और मोदी की मित्र जॉर्जिया मेलोनी ने यूपी के योगी मॉडल पर अमल करने की घोषणा की,

शामिल न होना, बायोफोर्टिफाइड फसलों की पहुंच को सीमित कर रहा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए कृषि अनुसंधान, विस्तार सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सप्लीमेंटेशन (पूरक आहार) और खाद्य फोर्टिफिकेशन (खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बढ़ाना) जैसे कार्यक्रमों के विपरीत, जिनमें लगातार निवेश की आवश्यकता होती है, बायोफोर्टिफाइड बीजों को बार—बार बोया और उगाया जा सकता है, जिससे ये बहुत किकायती साबित होते हैं। बायोफोर्टिफाइड किस्मों को लोकप्रिय पौएम पोषण (मिड—डे मील) और आंगनवाड़ी पूरक पोषण जैसे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। वैज्ञानिक तरीके से फसलों को विकसित करने, संस्थागत खरीद और लक्षित विस्तार सेवाओं

पहला, जमीन आवंटित करने से पहले पानी की उपलब्धता को

अकालन किया जाना चाहिए। किसी बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले, राज्य को जल संतुलन, प्रस्तावित



भूजल की स्थिति, पानी की अन्य प्रतिस्पर्धी मांगों और जलवायु संबंधी जोखिमों पर विचार करना चाहिए। दूसरा, जल उपयोग दक्षता को प्रदर्शन मापने का एक पैमाना (परफॉर्मंस मीट्रिक) बनाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन (इंसेंटिव) केवल वादा की गई तकनीक पर नहीं, बल्कि जल दक्षता (वाटर एफिशिएंसी) पर आध्ारित होने चाहिए। तीसरा, जहां भी संभव हो, उपचारित अपशिष्ट जल (ट्रीटेड वेस्टवॉटर) के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए हमेशा ताजे पानी (फ्रेशवॉटर) की जरूरत नहीं होती। पानी को रीसाइक्लिल और दोबारा इस्तेमाल करने से भूजल भंडार और नगर निगम की जलापूर्ति पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। चौथा, कर्नाटक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए जल—लचीलापन (वाटर—रेजिलिएंस) संबंधी नियम लागू कर सकता है। एक निश्चित सीमा से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए,

आर्थिक अवसर पानी पर आधारित टिकाऊ कूलिंग सिस्टम विकसित करना, अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल करना, गर्मी का प्रबंधन करना और कम कार्बन उत्सर्जन वाले डेटा सेंटर डिजाइन करना—ये सब कर्नाटक के लिए विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र बन सकते हैं।

अर्थिक अवसर

पानी पर आधारित टिकाऊ कूलिंग सिस्टम विकसित करना, अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल करना, गर्मी का प्रबंधन करना और कम कार्बन उत्सर्जन वाले डेटा सेंटर डिजाइन करना—ये सब कर्नाटक के लिए विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर ‘बुलडोजर मॉडल’ राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण हटाना और किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उसकी संपत्ति गिराना, दोनों अलग बातें हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट किया कि केवल किसी आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया को पालन किए बिना, किसी की संपत्ति गिराना असंवैधानिक है। न्यायालय ने नोटिस, सुनवाई और न्यायिक समीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए। लिहाजा, यूरोप में भी ऐसी किसी नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक समन्वय जैसे क्षेत्रों में उपयोगी अनुभव पाती हैं, तो तकनीकी सहयोग और नीतिगत संवाद के अवसर बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ बताते हैं कि इसे अभी एक संभावित दिशा समझना चाहिए, न कि यूरोप द्वारा योगी मॉडल स्वीकार कर लेने का प्रमाण! तीसरा अहम सवाल है कि क्या यूरोप में ‘बुलडोजर नीति’ भी अपनाई जा सकती है? तो जवाब होगा कि यहीं पर इस बहस का सारसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है।

है? इसे हमलोग विषय दर विषय, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश के मॉडल से जुड़ी बहस और यूरोपीय व्यवस्था की प्रमुख कसौटी के आधार पर निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। यूरोप की परिषद के मानवाधिकार मानकों में पुलिस कार्रवाई के लिए आवश्यकता, अनुपातिकता और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। ये मानक हिंसक घटनाओं से निपटने के साथ—साथ शांतिपूर्ण सभा के अधिाकार की रक्षा भी करते हैं। जहां तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसके संभावित प्रभाव की बात है तो इससे भारत की प्रशासनिक छवि मजबूत होगी। यदि उत्तर प्रदेश की किसी नीति से अपराध नियंत्रण या पुलिस—प्रशासन के समन्वय में मापने योग्य सुधार सिद्ध होता है, तो भारत अपने अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय नीति—चर्चाओं में प्रस्तुत कर सकता है। इससे भारतीय राज्यों के प्रशासनिक प्रयोगों पर शोध और संवाद को बढ़ावा मिल सकता है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सुनिश्च लोकतंत्र है, इसलिए भारत की बातों को अनसुनी करना अन्य देशों के लिए घातक भी हो सकता है।

रेलवे ट्रैक पर तरव्त् सव ट्रेन पलटाने की साजिश करने मे आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार कर भेजा जेल



अयोध्या रेलवे ट्रैक पर तख्त् रखकर ट्रेन पलटाने के मामले में जीआरपी अयोध्या कैंट ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में थानाध्यक्ष जीआरपी कैंट रेलवे स्टेशन अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपों की पहचान रौनाही थाना क्षेत्र के

मुस्तफाबाद बड़ागांव निवासी सुखेन्द्र उर्फ रिक्ू (32) पुत्र सत्येन्द्र कुमार के रूप में हुई है। बताया कि 29 अक्टूबर को थाना जीआरपी अयोध्या कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया कि आरोपी सुखेन्द्र उर्फ कि गिरफ्तार किए गए आरोपों की मोटें पुत्र विजय कुमार और आकाश

पुत्र गोली के साथ मिलकर ट्रेन संख्या 15054 डाउन को डिरैल करने के इरादे से रेलवे ट्रैक से तख्त उठाकर रख दिया था। मामले में तीनों को आरोपी बनाया गया था। बताया कि शुक्रवार रात करीब 12रू50 बजे रेलवे स्टेशन बड़ागांव से सुखेन्द्र उर्फ रिक्ू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक सौरभ वर्मा, कांस्टेबल प्रशांत सिंह, सचिन सिंह, विवेक कुमार मिश्रा और मंजीत सिंह के अलावा आरपीएफ पोस्ट रुदौली के चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव और कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा शामिल रहे।

डीजे के शोर में दबकर रह गया हाईकोर्ट का आदेश

सुल्तानपुर, संवाददाता। हाईकोर्ट का आदेश, प्रशासन की चेतावनी और ध्वनि मानकों का हवाला...सब बेअसर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा में मंगलवार रात शहर की सड़कों पर डीजे का शोर गूंजता रहा। घरों में लोग सो नहीं सके, शिकायतें बढ़ीं तो डीएम इंद्रजीत सिंह और एसपी विनीत जायसवाल को रात में खुद सड़कों पर उतरकर डीजे की आवाज कम करानी पड़ी। अधिकारियों के निर्देश के बाद भी कई जगह तेज आवाज में डीजे बजते रहे। ऐसे में ध्वनि नियंत्रण का भरोसा देने वाली केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के दावे भी सवालों के घेरे में आ गए।

शहर में करीब 160 प्रतिमाओं का विसर्जन होना था। मंगलवार रात देवी प्रतिमाओं के साथ 100 से अधिक डीजे शामिल थे। विसर्जन मार्गों के आसपास रहने वाले लोग तेज आवाज और कंपन से परेशान रहे। अधिकारियों ने कई स्थानों पर पहुंचकर डीजे संचालकों को आवाज कम रखने के निर्देश दिए। शहर में भ्रमण के दौरान एसपी की कुछ लोगों से नोकझोंक भी हुई। आवाज कम होने पर मामला शांत हुआ। डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा ने डीएम और एसपी के साथ घाटों और प्रमुख चौराहों पर सुस्खा व्यवस्था का जायजा लिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमा शोर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम, एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्धारित ध्वनि मानकों में डीजे बजाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। शहर में डीजे के शोर को लेकर उन्होंने केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति की विफलता और डीजे संचालकों की मनमानी पर सवाल उठाते हुए इसे जनपदवासियों की सेहत से खिलवाड़ बताया।

मेडिकल कॉलेज के सामने 120

डिसेबल से अधिक शोर घर फाउंडेशन के नितिन मिश्र के मुताबिक, कहीं भी ध्वनि मानकों का पालन नहीं किया गया। कोतवाली नगर के सामने डीजे प्रतियोगिता आयोजित हुई, जबकि मेडिकल कॉलेज के सामने 120 डिसेबल से अधिक आवाज में डीजे बजाया गया। संस्था ने 27 अक्तूबर को कोतवाली नगर में लिखित शिकायत दी है। बताया कि 30 अक्तूबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। इसी दिन डीजे से संबंधित जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

इन्होंने पेश किया मिशाल डीजे के शोर के बीच नवदुर्गा पूजा समिति बहराजपुर के पदाधिाकारियों ने अन्य समितियों के लिए मिशाल पेश की। समिति ने बिना डीजे के मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया, जिसकी सराहना हो रही है। हमारी समिति की ओर से विसर्जन यात्रा में पूरा सहयोग किया गया था।

हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत

सुलतानपुर, संवाददाता। सुल्तानपुर—रायबरेली हाईवे पर महेशरगंज बस स्टॉप के पास मंगलवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार कोतवाली देहात के करोमी निवासी मजदूर सुरेंद्र पाल (34) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना मंगलवार रात करीब 08:30 बजे हुई। परिजनों के अनुसार वह बाइक से अकेले अमेठी जिले के टिकरी गांव स्थित अपनी ससुराल जाने के लिए निकले थे। महेशरगंज बस स्टॉप के निकट पहुंचते ही वह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लगी। ग्रामीणों ने एंबुलेंस से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां पर उनकी मौत हो गई। धम्मौर थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन के बारे में पता नहीं चल सका है, रास्ते के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

दुर्घटना में घायल किसान ने दम तोड़ा भदैया। धरोली चौराहे के पास 20 अक्तूबर को कार की चपेट में आने से घायल स्थानीय निवासी किसान घनश्याम बरनवाल (50) की बुधवार भोर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वह बेकाबू कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। मंगलवार रात वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ था। बुधवार सुबह अचानक उनकी मौत हो गई। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

अपर जिला जज की कार पर हमला, बीएसएफ जवान गिरफ्तार

आगरा, संवाददाता। आगरा—अलीगढ़ हाईवे पर खंदौली स्थित मई चौराहे के पास अलीगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली मुस्तफा की कार में बाइक से टक्कर मारने के बाद हमले का आरोपी बीएसएफ जवान दिनेश को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 24 अक्तूबर को अलीगढ़ न्यायालय की कोर्ट में तैनात अपर जिला जज अली मुस्तफा पिता गुलाम मुस्तफा, मां और गनर के साथ लखनऊ से अलीगढ़ जा रहे थे। खंदौली इंटरचेंज से उतरकर आगरा—अलीगढ़ हाईवे पर आए थे। मई चौराहे के पास पीछे से आए

बाइक सवार ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। उन्होंने बाइक सवार को समझाने का प्रयास किया था। आरोप है कि बाइक सवार ने गाली—गलौज करते हुए 30—40 लोगों को बुला लिया। अपर जिला जज, उनके पिता और गनर के साथ मारपीट की। हमलावरों ने कार का पिछला शीशा भी तोड़ दिया। कार में आग लगाने और जान से मारने की कोशिश करने का भी प्रयास किया था। वह किसी तरह बच सके थे। मामले में एक नामजद सहित 40 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीपी एल्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि आरोपी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपना नाम भूपेंद्र निवासी गोविंदपुर बता रहा था। इस आधार पर नामजदगी की गई। जांच में पता चला कि आरोपी का असली नाम दिनेश है। वह खंदौली के ही गांव बुर्ज पैंतखेड़ा का रहने वाला है। वह बीएसएफ में पंजाब में तैनात है। वह छुट्टी पर आया हुआ था। बाइक लेकर जा रहा था। तभी घटना कर दी। मामले में पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है। अज्ञात आरोपियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। आरोपी को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

आगरा की हवा में घुला जहर – बारह खंभा में एक््यूआई 413

आगरा, संवाददाता। दिवाली से पहले घर की सफाई में निकल रहा कचरा जलाने, सीएम ग्रिड की सड़कों से उड़ रही धूल, ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों ने प्रदूषण बढ़ा दिया है। शहर के 39 चौराहों में से 32 में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रहा है। इनमें 13 चौराहों पर बेहद खराब और 19 पर खराब स्थिति रही। आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर्स में अर्जुन नगर तिराहे पर बारहखंभा रेलवे पुल की खोदाई के कारण एक््यूआई 413 दर्ज किया गया, जबकि शहीद नगर में 391 और राजामंडी में 361 दर्ज किया गया। दोनों जगह सीएम ग्रिड के तहत खुदाई चल रही है। जाम, निर्माण कार्य और टूटी सड़कों के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में फतेहपुर सीकरी और शहर में रोहता की हवा सबसे खराब रही।

जनपद के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 24 वीं किस्त अन्तरित’

‘ब्यूरो रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव’ हरदोई। शुक्रवार को मां प्रेानमंत्री भारत सरकार द्वारा बनासकांठा, गुजरात से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24 वीं किस्त किसानों के खाते में आनलाइन स्थानान्तरित की गई। जिसका सजीव प्रसारण जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों विकास खण्ड मुख्यालय पर, जनपद में स्थित दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों, समस्त किसान समृद्धि केंद्रों मण्डी स्थलों पर, समस्त कृषक उत्पादक संगठन के कार्यालयों, उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं जनपद स्तर पर किया गया। जनपद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कृषक सभागार, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, बिलग्राम चुंगी, हरदोई पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। जिलाधिकारी का कृषि विभाग के अधिकािरियों द्वारा पुष्प गुच्छ एवं स्वागत संबोधन के साथ सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जी द्वारा कृषको को सम्बोधित करते हुये कहा कि सम्बोधित करतें हुये नारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना हमारे कृषक भाईयों के लिये बहुत ही उपयोगी योजना है। उनके द्वारा उपस्थित कृषि सखियों एवं महिला कृषको को सम्बोधित करते हुये नारी संशक्तीकरण पर जोर दिया तथा कृषि सखियों, ड्रोन दीदीयों के द्वारा कृषि क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई। आयोजित कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डा० राजेश कुमार ने किसानों को बताया गया कि जो पात्र कृषक है वे अपना पीएम किसान योजना में पंजीकरण कर योजना में जुड सकते है, इसी के

नराशि से अपनी फसल के उत्पादन के लिये बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश को क्रय करने में मदद मिलती है। जिससे कृषको को खेती किसानी का कार्य समय से करने में मदद मिलती है तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है तथा आय में वृद्धि होती है। उनके द्वारा बताया गया कि कृषक जैविक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, श्री अन्न फसलों की खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते है। उन्होंने कृषकों से अधिक से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, करने का आह्वान किया गया। उनके द्वारा किसानों से प्रत्येक दशा में फार्म रजिस्ट्री करने का भी अनुरोध किया गया। अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा संजय मिश्रा जी द्वारा कृषकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना हमारे कृषक भाईयों के लिये बहुत ही उपयोगी योजना है। उनके द्वारा उपस्थित कृषि सखियों एवं महिला कृषको को सम्बोधित करते हुये नारी संशक्तीकरण पर जोर दिया तथा कृषि सखियों, ड्रोन दीदीयों के द्वारा कृषि क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई। आयोजित कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डा० राजेश कुमार ने किसानों को बताया गया कि जो पात्र कृषक है वे अपना पीएम किसान योजना में पंजीकरण कर योजना में जुड सकते है, इसी के

मोटुल इंडिया ने अयोध्या में सेहत की समृद्धि हेल्थ कैंप का आयोजन किया



ब्यूरो से लिफ आर एल पाण्डेय अयोध्या। प्रीमियम इंजन और औद्योगिक लुब्रिकेंट बनाने वाली प्रमुख कंपनी मोटुल इंडिया ने अपनी देशव्यापी स्वास्थ्य पहल सेहत की समृद्धि के तहत अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हेल्थ कैंप का आयोजन किया। सेहत की समृद्धि के तहत 27 जिलों में कुल 108 हेल्थ कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के जरिए देशभर में 21,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस अभियान के तहत अयोध्या में भी कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 205 लोगों को लाभ मिला और 100 से ज्यादा हेल्थ किट बाँटी गई।

मोटुल इंडिया और साउथ एशिया के सीईओ नार्गेंद फिलो ने कहा कि सेहत की समृद्धि इस सोच को दर्शाता है कि भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को आगे बढ़ाने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का दायरा बढ़ रहा है और हमें खुशी है कि हम शहर के ऑटो मैकेनिकों और उनके परिवारों तक सीधे निवारक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। स्माइल फाउंडेशन के को—फाउंडर सांतनु मिश्रा ने कहा कि सेहत की समृद्धि इस बात का अच्छा उदाहरण है कि जब कॉरपोरेट प्रतिबद्धता जमीनी स्तर

साथ उनके द्वारा जनपद के समस्त कृषकों से अपील की गयी कि सभी कृषि अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें एवं साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल सुश्का तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने किसानों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का सजीव प्रसारण जनपद के समस्त विकास खण्डों, कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम, हरदोई व द्वितीय, सण्डीला, पाठक, डा० निधि रावौर, भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय, जिला सूचना अधिकािरी प्रशान्त अवस्थी ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान, बी०डी०सी० सदस्यों, प्रगतिशील कृषकों, पुरस्कृत कृषकों कृषि सखी, बैंक सखी, ड्रोन दीदी द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। जनपद के समस्त एफ०पी०ओ० के कार्यालयों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें एफ०पी०ओ० से जुड़े हुये कृषकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

खराब मौसम के बावजूद पीईटी परीक्षा में 18,078 अभ्यर्थी हुए शामिल,7,026 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

अयोध्या। पीईटी परीक्षा शुक्रवार को जिले में दो पालियों में संपन्न हुई।खराब मौसम के बावजूद अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया।हालांकि, बारिश के चलते कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।वहीं, परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहे और परीक्षा केंद्रों का जायजा लेते रहे।डीआईओएस कार्यालय के मुताबिक शुक्रवार को प्रथम पाली में 12,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे,जिनमें 9,061 उपस्थित और 3,491 अनुपस्थित रहे।द्वितीय पाली में भी 12,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे,जिनमें 9,017 उपस्थित और 3,535 अनुपस्थित रहे।दोनों पालियों को मिलाकर कुल 25,104 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 18,078 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 7,026 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण

‘ब्यूरो रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव’ हरदोई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शुक्रवार को जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने प्रथम पाली की परीक्षा के



दौरान राजकीय इण्टर कालेज हरदोई का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरों के संचालन की स्थिति, आदि का भी गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं शासन से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा सम्पन्न करायी जाय। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्बन्धित अधिकारी भ्रमणशील रहते हुए गहन निगरानी सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान पुलिस क्षेत्राधिाकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

रेड क्रॉस कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए विशेष आधार शिविर का हुआ आयोजन

ब्यूरो रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव’ शाहजहांपुर। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रांगण स्थित इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यालय



में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए विशेष आधार शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन आ्हार सेवा केंद्र, शर्मा जी का डेरा, चार।

ओटीएस के तहत 90 दिन में टैक्स जमा करना अनिवार्य

बरेली, संवाददाता। बरेली में नगर निगम की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में आवेदन करने के बाद टैक्स जमा करने में देरी की तो ब्याज माफी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब तक 14,283 शहरवासियों ने आवेदन किया है। इनमें से 10,863 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 3,362 आवेदन प्रक्रिया में हैं। योजना के तहत निर्धारित 90 दिनों में पूरा टैक्स जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा बकाया और ब्याज की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। नगर निगम में 15 अगस्त से चल रही ओटीएस योजना के तहत अब तक 31.41 करोड़ रुपये की डिमांड का निस्तारण हुआ है। इसमें 8.69 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है। योजना के तहत आवासीय भवनों के 11,087 और व्यावसायिक भवनों के 886 आवेदन मिले हैं। वहीं, 2,330 आवेदन आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों से संबंधित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2.50 करोड़ और ऑनलाइन माध्यम से 17.52 लाख रुपये जमा हुए हैं।

युवक ने खाया जहरीला पदार्थ

बरेली, संवाददाता। बरेली में एक युवक अपनी पत्नी की मौत के दो साल बाद भी उसका गम दिल से नहीं निकल सका। करवाचौथ पर पत्नी की याद आई तो किला क्षेत्र के चाहबाई निवासी सूरज कश्यप ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत में सुधार है।

साम्न्ध हिन्दी दैनिक	देश की उपासना
<p>स्वात्वाधिकारी में, प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।</p> <p>सम्पादक</p> <p>श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव</p> <p>मो0 – 7007415808, 9415034002</p> <p>Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com</p>	
<p>समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।</p>	